Rift in the Centre for advanced study in Metallurgy at Banaras Hindu University

1056. SHRI PARVATHANENf UPENDRA:
SHRI VIRENDRA VERMA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is a rift between the Banaras Hindu University and the University Grants Commission over the person to head the Centre for Advanced Study in Metallurgy the Banaras Hindu University; and

(b) if so, what action has been taken by Government to resolve the rift t° prevehf closure of this prestigious institution?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) and (b) According to the information fur^ nished by the University Grants Commission, Prof, T. R. Ananthai aman was Coordinator of the Centre of, need Study in Metallurgy at Banaras Hindu University before his superannuation on 30-11-87. Consequent to his superannuation the rnat-rding the Programme Coordi-natorship of the Centre of Advanced Study in Metallurgy was discussed by the Executive Council of Banaras Hindu University on 5th December, 1987. The Council resolved to authorise the Vice-Chancellor to make necessary arrangements for Programme Coordinator. The Vice-Chancellor asked the Head of the Department of Metallurgical Engineering to function as Programme Coordinator of the Centre in Place of Port T. R. Anan-tharaman.

The University Grants Commission has asked the University to review their decision m the light of its guidelines governing the appointment oi Programme Coordinators under the Special Assistance Programme,

रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रस्ताव

1057. श्री प्रमोद जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यालय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसा कोई संशोधन करने का विचार कर रही है जिसमें छात्र हाई स्कूल परीक्षा पास करने से पूर्व कम से कम एक व्यवसाय या तकनीक में निपुणता हासिल कर सकें और वे शिक्षा प्राप्ति के बाद बेकार न रहें;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) इस समय विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों में प्रतिवर्ष कितने छात्र दाखिल किये जा रहे हैं और कुल छात्रों में उनका प्रतिशत कितना है; और

(घ) उक्त संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही): (क) व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में बहुत ही उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इसमें इसके साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि "व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी विशिष्ट शिक्षा होगी जिसका आशय विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुये अनेक पहचाने व्यवसायों हेतु छात्रों को तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम सामान्यत: माध्यमिक स्तर के पश्चात् पढ़ाये जायेंगे, लेकिन योजना को लचीला रखते हुये, ये शिक्षा VIII के पश्चात् भी उपलब्ध कराये जा सकते हैं।"